भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका
वर्ष 30 अंक (1) जून 2022 पृ. 23-33

भारत सरकार के 'कौशल भारत' और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों की सफल पूर्ति में सूचना, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और वैज्ञानिक प्रगति का महत्व

शुभम परसोया
संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान) 311 001

सारांश : 'मेक इन इंडिया' अभियान और 'स्किल इंडिया' अभियान को भारत सरकार द्वारा समन्वित और प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय आबादी को बेहतर जीवन शैली प्रदान करना और प्रति वर्ष वेतन वृद्धि करना था। भारत की प्रति व्यक्ति आय और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल राष्ट्रीय उत्पादन (सकल घरेलू उत्पाद) को बढ़ाने के लिए। देश के कार्यबल का उचित सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आधारित कौशल विकास गुणवत्ता मानदंडों के निर्माण और दुनिया भर के बाजार स्तरों पर सामान्य प्रदर्शनी स्तरों में स्थिरता प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली पहल हो सकती है। इसके अलावा, यह भारत को ''पांच ट्रिलियन डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था" बनाने के उद्देश्य को पूरा करने की गति को भी उन्नत करेगा। भारत जैसे राष्ट्र के रूप में बुनियादी सुविधाओं के वांछित स्तर की उन्नति के लिए नवीनतम और आधुनिक तकनीकों से लाभ प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए बहुत बड़े स्तर के निवेश की आवश्यकता होती है, हालांकि सक्षम कार्यबल के आवश्यक स्तर की उपलब्धता के बिना, कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय विकास और आर्थिक सुधार के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है, और विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने और असेम्बलिंग फ्रेमवर्क के क्षेत्र में बदलाव को सशक्त बनाने के लिए कुशल और सक्षम कार्यबल की आदर्श डिग्री की पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के कौशल स्तरों में सुधार करने की क्षमता राष्ट्र को अन्य देशों से अधिक धन और निवेश लाभ इकट्ठा करने के लिए उन्नत करेगी। 'मेक इन इंडिया' अभियान और 'स्किल इंडिया' अभियान को प्रभावी बनाने, भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने और उसमें शामिल होने में भारत सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों ने कार्यबल के लिए ''कौशल विकास कार्यक्रम'' की आवश्यकता को कई हद तक बढ़ा दिया है। यह समझना और निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौशल विकास क्षमता के मौजूदा स्तर भारत के समग्र विकास और विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों के रास्ते में आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों को यथाशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत की कौशल क्षमताओं के वर्तमान स्तर का विश्लेषण करना और भारत के विकास के रास्ते में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का पता लगाना है। भारत सरकार की कौशल विकास योजना और विकास रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए नियोजन उन्नयन में निरंतरता के साथ-साथ प्रभावी कौशल विकास प्रणालियों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है।

Significance of information & computers technology (ICT) and scientific advancementsin the successful accomplishment of the objectives of 'Skill India' & 'Make in India' programme of government of India

Shubham Parsoya
Sangam University, Bhilwara, Rajasthan 311 001

Abstract

The Make in India drive and Skill India drive were coordinated and presented by the Government of India which was intended to give an improved degree of work openings, giving a superior way of life to the Indian population, and increment in the per capita income of India. And also, to increase the total national output (Gross domestic product) of the Indian economy. Proper information and computers technology (ICT) based skill development of the workforces of the country can give a powerful grasp on the creation of quality norms and for giving maintainability in the general exhibition levels at all worldwide market levels. Furthermore, it will also upgrade the speed of accomplishing the objective of making India a Five Trillion Dollar based Economy. As a country like India, requires a very large level of investment for availing and utilizing the benefits of the latest and modern technologies for the advancement of the desired level of infrastructure facilities.however, without the availability of the required level of the capable workforceand Scientific Advancements, no nation can accomplish its objective of national

development and economic improvements. And for attracting foreign investors to invest in India, and for empowering changes in the field of assembling framework set up, accessibility of the ideal degree of the skilled and capable workforce is very significant. The ability to make improvements in the skill levels of any country will upgrade the nation to gather more money and investment benefits from other countries.For making the Make in India drive and the Skill India drive effective, the Government of India needs to face a huge number of challenges in fulfilling and attending the target of making India a Five Trillion Dollar based Economy. Such situations increased the necessity of Skill Development Programs for the workforce. It is very significant to understand and determine that the current levels of skill development capacities are not sufficient for the overall growth and development of India. The problems and challenges in the ways of Skill Development Programs need to be corrected as soon as possible. The objectives of this research paper are to analyse the present level of skill capacities of India and to ascertain the various challenges coming in the way of the growth and development of India. The availability of effective skill development systems along with consistency in the planning upgradation is very important for the successful implementation of skill development planning and development strategies of the government of India.

प्रस्तावना

कौशल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। भारत में कौशल विकास न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से भी आवश्यक है। किसी भी देश के लिए कौशल और ज्ञान, उसके सामाजिक-आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय विकास की प्रमुख प्रेरक शक्ति होती है। वर्तमान परिदृश्य में, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं को गुणवत्ता के वैश्विक मानक और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर संचालन के लिए एक कुशल और जानकार कार्यबल की आवश्यकता है। कुशल कर्मचारी किसी भी देश के व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और यह किसी भी देश के घरेलू उद्योगों में उन्नत तकनीकों को लाने में सहायक भूमिका निभाते हैं जो ऐसे देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुशल, बहुआयामी और कौशल विकास प्रणाली की अधिक उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के विकास के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध में वैश्विक कार्यबल विकास एक प्रमुख योगदानकर्ता साबित होगा, और यह भारत को ''पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था'' बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को बढ़ाने में मदद करेगा। चीन में 37 वर्ष और यूरोप में 45 वर्ष की औसत आयु की तुलना में 29 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे कम उम्र की आबादी होने के साथ ही अन्य विभिन्न लाभों के साथ-साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वैश्वीकरण और उच्च-स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक स्तर के ज्ञान के साथ एक उच्च कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, और यह न केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि विकसित राष्ट्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह की वृद्धि एक देश को नए विकास की ओर ले जाने और अर्थव्यवस्था के विकास स्तर और व्यवसायों के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

यह देखा गया है कि जिस देश में उच्च प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल मौजूद होते है वह राष्ट्र हमेशा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के उच्च स्तर के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्राप्त करता है। और कुशल श्रम बल वाले देशों में कार्य स्तरों पर आवश्यकताओं के अनुसार चुनौतियों और अवसरों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से समायोजन की क्षमता होती है। लेकिन प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने के लिए केवल बड़े आकार के कार्यबल का होना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास ऐसे कार्यबल को नौकरी के अवसरों और वास्तविक बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्णित अध्ययन के उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, अध्ययन के लिए लागू किया गया शोध पैटर्न वर्णनात्मक प्रकार का है। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का

उपयोग अध्ययन के लिए पूर्ण और व्यापक रूप से किया गया है। उपलब्ध संसाधनों के अध्ययन में अधिक सटीकता और विषय से संबंधित गहन विश्लेषण पर विचार किया गया है। रोजगार के संबंध में कौशल विकास की भूमिका का अध्ययन करने और इस तरह से चुनौतियों और बाधाओं का विश्लेषण करने के साथ-साथ भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल और 'स्किल इंडिया' पहल का सफलता से अध्ययन और गहन विश्लेषण किया गया है। यह शोध पत्र खोजपूर्ण शोध तकनीक पर आधारित है, जो कि प्राप्त जानकारी, पुस्तकालयों की पत्रिकाओं, विश्वसनीय पत्रिकाओं, विभिन्न प्रकार की अन्य पत्रिकाओं, प्रासंगिक पुस्तकों, विषय-संबंधित लेखों, मीडिया के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट, भारत सरकार के 'मेकइन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' के संभावित पोर्टलों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में कार्यबल के वर्तमान कौशल क्षमता स्तर का अध्ययन करना, ताकि कुशल श्रम बलों की वास्तविक उपलब्धता के साथ-साथ कौशल अंतराल की उपस्थिति के बारे में विश्लेषण किया जा सके।
- वैश्विक आउटसोर्सिंग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की पहलों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय कार्यबल को अधिक कुशल और सक्षम बनाने में भारत सरकार द्वारा किए गए योगदान का विश्लेषण करना।
- भारत के कौशल विकास की समग्र प्रणाली में सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का अध्ययन करना, जो भारत सरकार के ''पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाओं की तरह कौशल अंतराल की उपस्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- 'मेक इन इंडिया' परियोजना को सफल बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10% सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौशल विकास की समग्र प्रणाली के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का अध्ययन करना।
- भारत में कौशल विकास प्रणाली और कार्यबल की कौशल क्षमता की वर्तमान स्तर की स्थिति और कौशल विकास कार्यक्रमों के संबंध में वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण करना।
- इस तरह की चिंता में संभावित समाधानों के बारे में सुझावों के साथ-साथ संभावित सुधारात्मक कदमों का पता लगाने के संभावित तरीकों का पता लगाना।

अध्ययन की सीमाएं

कौशल विकास और सापेक्ष उद्देश्यों के विश्लेषण के लिए, सभी उपलब्ध स्रोत से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है जो कि इसके बिंदु से सत्य मानी जाती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समान परिणाम समग्र रूप से और समकक्ष तरीकों से हर जगह जनसंख्या के लिए समान रूप से प्रभावी होंगे। संसाधनों व तथ्यों की निरंतर खोज और गतिशीलता के कारण, कोई भी शोधकर्ता हमेशा इन सभी संसाधनों से पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकता है। साथ ही कोई भी शोधकर्ता इन शोधों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार इन सभी आँकड़ों को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, जो कि शोध की पूर्व निर्धारित समय व योजना को प्रभावित कर सकता है।

जिसके कारण अनुसंधानकर्ता अनुसंधानों के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को एकत्रित नहीं कर सकता है, जो उपर्युक्त संसाधनों पर आधारित होते हैं। जिस कारण शोधार्थी इन संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों का अनुसंधान व विश्लेषण के लिए प्रयोजन मात्रा ही कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसाधन दुर्लभ हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। और किसी भी कार्य को उपलब्ध सीमित समय में पूरा करने के लिए कुछ मानक और प्रतिमान उपस्थित होते हैं, जिनका पालन करना शोधकर्ता के लिए अनिवार्य होता है।

इस तथ्य पर विचार करने में यह शायद एक परेशानी है कि हमारे पास हमेशा उपर्युक्त वह सभी संसाधन नहीं हो सकते हैं जो हमें अनुसंधान व विश्लेषण के लिए चाहिए होते हैं। यह किसी भी चीज के कारण हो सकता है जैसे कि गैजेट्स की कमी, कुछ संसाधनों की अनुपलब्धता, और शोध करने के लिए सीमित समय, राशि आदि। परिणाम कुछ स्थितियों में भिन्न हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ता किस तरह से रिकॉर्ड एकत्र करता है और समाधान होने के संबंध में डेटा एक वास्तविक सीमा पैदा कर सकता है। डेटा की गुणवत्ता अक्सर और तद्नुसार तकनीक अनुसंधान पर निर्भर करती है, और जब एक शोधकर्ता कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशेष शोध तकनीक का उपयोग करके कुछ नई जानकारी प्राप्त करता है तब विभिन्न तकनीकें शोधकर्ता को विभिन्न अवसर प्रदान कर सकती हैं।

लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह में चुनौतियां

भारतीय कार्यबल के आकार के अनुसार, भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य

करने के लिए केवल बड़े आकार के कार्यबल का होना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना ऐसे कार्य बल को नौकरी के अवसरों और वास्तविक बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ने में बहुत प्रासंगिक भूमिका निभाते हैं। भारत एक युवा देश है जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। ऐसी स्थिति एक अवसर या चुनौती बन सकती है। चूंकि ऐसी युवा आबादी का देश पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही उत्पादक कार्यबल दाता की क्षमता के रूप में भूमिका निभा सकता है, और यह पूरी दुनिया के सामने ''जनसांख्यिकीय लाभांश" का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित कर सकता है।

कार्यबल में आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल स्तर के बीच बेमेल होने के कारण, वर्तमान में, देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता के मामले में किसी तरह पीछे हैं। इसका परिणाम आर्थिक रूप से निष्क्रिय कामकाजी आयु वर्ग के लोगों में भी हो सकता है, जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज पर विभिन्न गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता हैं। जनसांख्यिकीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत में कौशल पहल के उचित कार्यान्वयन के लिए गुणवत्ता, मात्रा और नौकरी के अवसरों के लिए एक कुशल कार्यबल की पहुंच सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

2009 के अनुसार, वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस तरह की पूर्ति के लिए, कौशल विकास क्षमता के स्तर को 3.1 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12 मिलियन कर दिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में कौशल विकास के लिए अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रमाणन आधारित प्रणाली स्थापित करना एक जटिल कार्य है। भारत की 65% से अधिक जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम उम्र की है, और उनमें से अधिकांश गैर-कामकाजी हैं और अन्य बेरोजगार हैं। सरकार ने वांछितों को व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना की। इस कार्यक्रम में व्यावसायिक, सामान्य, तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न प्रवेश और निकास विकल्प उपलब्ध किए हैं, ताकि व्यक्ति आसानी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैरियर विकल्प चुनने का विकल्प चुन सके।

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, औद्योगिक दृष्टिकोण से कौशल और ज्ञान की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी परिवर्तन होते हैं। प्रमाणन कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम, नौकरी आधारित प्रशिक्षण सहित पाठ्यक्रम उद्योग की वास्तविक जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने में होने चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से छात्र और स्नातक जो प्रमाणपत्र और पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे हैं, वे आवश्यक मानकों के मौजूदा स्तर के साथ तालमेल से बाहर हैं। शिक्षित कुशल श्रम और कार्यबल की कमी के कारण, कई बार उद्योगों को नौकरी के लिए सही उम्मीदवार खोजने में और सही समय पर सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति की भर्ती करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण अधिकांश समय इन

उद्योगों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त स्तर का प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए अपनी ओर से बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने पड़ते हैं। यह समग्र उत्पादकता को बाधित करेगा और साथ ही उत्पादन की लागत में वृद्धि करेगा।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक पेशेवर प्रशिक्षकों की उपलब्धता है, क्योंकि पेशेवर प्रशिक्षकों के पास वांछित मानकों के अनुसार शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की विशेषज्ञता होती है। लेकिन किसी तरह उचित प्रशिक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण जिनके पास पर्याप्त कौशल और विशेषज्ञता है, भारत जैसे विकासशील देश में एक चुनौती बन गई है। और इसका समाधान खोजने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा शिक्षा क्षेत्र में रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अंतर्गत, वर्ष 2022 तक 8 मिलियन से अधिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों की वृद्धिशील आवश्यकता होगी।

इन सभी कठिनाइयों के साथ-साथ अन्य समस्याएं भी मौजूद हैं। भारत के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रीय क्षेत्रों के कारण और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से घिरे दुर्गम भूभाग के परिणामस्वरूप, आवश्यक मानक के अनुसार कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध उपायों को लागू करना अधिक कठिन बन जाता है। और भूभाग और विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह बाधाएँ शिक्षार्थियों के सामने भी कठिनाई खड़ी कर रही है।

भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, और इन सभी लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित विभिन्न प्रकार के खर्चों को छोड़कर उपर्युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के खर्चों को वहन करना लगभग असंभव है। इनमें से लगभग 90% लोगों के पास किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है और इनमें से केवल 1.5% ने ही प्रमाणन के साथ-साथ कोई औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस तरह भारत सरकार को कौशल विकास के मामले में गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत के लिए भविष्य के मार्ग एवं अवसर

कुशल और योग्य कार्यबल की वास्तविक मांग और वास्तविक आपूर्ति के बीच निरंतर चौड़ी और गहरी होती जा रही खाई की उपस्थिति वास्तव में न केवल विकसित देशों की बल्कि, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के सामने भी एक महत्वपूर्ण समस्याग्रस्त स्थिति है। दुनिया के सभी देशों में भारत देश की आबादी सबसे ज्यादा युवा हैं, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। लेकिन भविष्य में ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि दुनिया सहित भारत की आबादी की औसत उम्र भी दिन-बे-दिन बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या के 1.3 बिलियन लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक पहुंच जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि इतनी उम्र में पहुंचने तक बहुत से लोग विभिन्न कारणों के चलते श्रम और रोज़गार के रूप में काम नहीं कर पाते हैं, और इस उम्र में अधिकांश लोग सेवानिवृत्त होने को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

इसका तात्पर्य है कि अगर कोई देश जिसकी अधिकतम जनसंख्या युवा वर्ग में आती है, और इसके बावजूद भी अगर वह देश अपनी युवा आबादी का फायदा नहीं उठा रहा है, तो उसे अंततः इस कृत्य का पछतावा होगा, क्योंकि युवा वर्ग की आबादी ऊर्जा और क्षमताओं से भरी हुई होती हैं। और अगर ऐसी क्षमताओं को काम में बदल दिया जाए, तो इससे अधिकांश लोग के साथ ही देश को भी अत्यंत फायदा होता है।

विभिन्न विकसित राष्ट्र कुशल श्रम के मामले में लगातार मांग-आपूर्ति के अंतर के बढ़ने जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, भारत देश दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जिसमें कौशल और ज्ञान का बहुत अच्छा स्तर मौजूद है। इस सन्दर्भ में भारत अपनी युवा आबादी और कार्यबल को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके भारत की युवा आबादी को जनशक्ति के निर्यातक के साथ-साथ, सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र के रूप में एक प्रमुख निर्यातक बन सकता है। इससे भारत देश स्वयं को वैश्विक स्तर की लगातार बढ़ती हुई कार्य बल सम्बंधित आवश्यकताओं व मांगों को पूरा करने के लिए एवं स्वयं को मानव संसाधन भंडार का एक मजबूत दावेदार बना पायेगा। और अंततः यह भारत को ''पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत को ''पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिक्रियाएँ शानदार हैं। सरकार ने वास्तव में इस तरह के एक महान उद्देश्य के महत्व को महसूस किया और तदनुसार 2009 में ''राष्ट्रीय कौशल नीति" तैयार की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के 500 मिलियन लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना था। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का गठन सभी नीति निर्देशों और उसी के संबंध में समीक्षा के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में किया गया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए युवाओं और अन्य लोगों को पर्याप्त और आवश्यक स्तर का कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ कार्य करने के लिए सीखने की क्षमताओं का विकास करना है, जिसके परिणामस्वरूप एक निश्चित समय और ऊर्जा के भीतर महान स्तर का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाता है। समकालीन और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ, कई देशों ने अपनी आबादी को आवश्यक कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है ताकि उन लोगों को अपनी आय क्षमता बढ़ाने का मौका मिले। कौशल विकास का समग्र लक्ष्य एक ऐसा कार्य बल तैयार करना है जो सभी आवश्यक और लगातार उन्नत कौशल, ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ सशक्त रोजगार के अवसरों का आकलन करने और इस गतिशील वैश्विक बाजार में महान प्रतिस्पर्धी लाभों के साथ देश को वास्तविक तोर से सशक्त बनाने से है।

भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ''मेक इन इंडिया" पहल की निरंतर उपलब्धि के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में सतत विकास के उपर्युक्त सरकारी लक्ष्य में सफल होने में बड़ी संख्या में चुनौतियां मौजूद हैं। चूंकि ''मेक इन इंडिया" पहल का प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारी क्षमता के साथ-साथ भारत के मूल

निवासी के कौशल विकास के अवसरों से भी संबंधित है। इस लगातार उभरती हुई गतिशील और वैश्वीकृत दुनिया में बड़ी तेजी से डिजिटलीकरण अपना दायरा बड़ा रहा है, इसलिए कोई भी देश केवल किसी योजना को तैयार करके दूसरों के सामने खुद को 'एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र' बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, इस तरह की योजना का उचित कार्यान्वयन प्रमुख भूमिका निभाता है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रदर्शन के मौजूदा स्तर के अलावा, गुणवत्ता मानकों के अनुसार कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की गति में कुछ वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि भारत ''एक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। भारत सरकार भी ''5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था" के लक्ष्य को प्राप्त करने के समग्र दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, बुनियादी ढांचे की चुनौती को बहुत शानदार ढंग से संभाल रही है। सरकार रेलवे, परिवहन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है, इसके साथ ही, सरकार ने इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाले सभी दिक्कतों को दूर करने के साथ-साथ लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए अनेक असाधारण सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

'फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल 'व्हाइट-कॉलर' और 'ब्लू-कॉलर' जॉब आवश्यक है, बल्कि 'ग्रे-कॉलर' जॉब्स भी एक असाधारण भूमिका निभाएंगे। 'ग्रे कॉलर' नौकरियों में आईसीटी कौशल, समस्या सुलझाने के कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, प्रभावी संचार कौशल आदि ज्ञान शामिल हैं। और इस तरह के 'ग्रे कॉलर' जॉब को कवर करने के लिए, सर्वोत्तम कौशल-आधारित सरकारी प्रशिक्षण केंद्र और विभिन्न उद्योग जगत के नेता इसके बारे में सभी आवश्यक कौशल और पर्यावरण प्रदान करने के लिए एक ठोस योजना के साथ कार्य कर रहे हैं।

जिसके लिए उचित निगरानी और गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान किये जा रहे हैं, जो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर मुख्य ध्यान देने के साथ उच्चतम मानक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाने के साथ-साथ इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, कुशल कार्यबल की आवश्यकताएँ बहुत जरूरी हैं। देश के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' को बदलने के साथ-साथ इस उभरते आर्थिक वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उचित और आवश्यक कौशल आधारित प्रशिक्षण विकास प्रणाली समय की आवश्यकता है।

भविष्य के अनुसंधान और अध्ययन के अवसर

- भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यबल और बेरोजगारों को पर्याप्त स्तर के सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित कुशल प्रशिक्षण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजित कौशल विकास पहल के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण करना है।
- भारत सरकार की विभिन्न कौशल विकास और वैज्ञानिक प्रगति संबंधी पहलों की कार्यान्वयन प्रक्रिया के बीच आने वाली चुनौतियों, समस्याओं, कमियों के संबंध में वर्तमान वास्तविक परिदृश्य का अध्ययन।
- कौशल विकास पहल और कार्यबल विकास कार्यक्रम के सभी पहलुओं का विश्लेषण करना है, ताकि वैज्ञानिक प्रगति संबंधी वास्तविक परिदृश्य की उचित झलक हमारे सामने आ सके।
- किसी भी स्थिति से संबंधित समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब आपको उसकी उचित समझ हो। इसलिए किसी भी मुद्दे का समय पर और व्यवस्थित आधार पर समाधान करने के लिए संबंधित डेटा की उचित उपलब्धता और विषय पर विस्तृत अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।
- मेरा वर्तमान अध्ययन भारत सरकार की सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित पहलों के वास्तविक प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन के अवसर और ऐसे वैज्ञानिक प्रगति आधारित कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास कार्यक्रमों के अध्ययन के अवसर जिसके माध्यम से कार्यबल द्वारा लाभ अर्जित और संचालित होते हैं। ताकि वास्तविक प्रदर्शन संबंधी जानकारी का विश्लेषण किया जा सके, जो बीच में आने वाली किसी भी कमी के साथ वास्तविक प्रदर्शन स्तर की व्याख्या करने में सक्षम साबित हो सके।

संदर्भ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Skill_India
2. http://www.mapsofindia.com/my-india/society/skill-india-a-new-programme-to-belaunched-in-march-2015
3. http://msde.gov.in/nationalskillmission.html
4. http://www.nationalskillindiamission.in/
5. www.skillindia.in

6. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, (FICCI 2010), *The skill development landscape in India and implementing Quality skills training*, Zugriff am 19 April 2012.
7. Parsoya, Shubham & Perwej, Asif, Present requirements of drawing up necessary changes in our petroleum usage to alleviate the detrimental aftermath of environmental contamination. The Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)-National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR), Bharatiya Vaigyanik Evam Audyogik Anusandhan Patrika (BVAAP), **29**(1) (2021), 14-18.
8. Houghton J & Sheehan P, A Primer on the Knowledge Economy, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, February (2000).
9. FICCI The Skill Development Landscape in India and Implementing Quality Skills Training, New Delhi: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (2010).
10. National Policy on Skill Development, Ministry of Labour and Employment, Government of India. Retrieved 28 September 2013, from available at http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Policies/National Skill Development PolicyMar09.pdf (2009).
11. Parsoya Shubham, Parsoya Priyanka, & Perwej, Asif Future Business Prospects and Marketing Strategies of Oil and Energy Marketing Companies (Under Government of India), *Vidyawarta* **09**(33) (2020).
12. Skill development Sector, FICCI, 2012http://www.ficci.com/sector/74/Project_docs/SectorProfile.pdf
13. Biswajit Saha, "Knowledge Management: Strategy, Technology and Application", Proc. of Intl. Conf. on Information Management (ICIM) in a Knowledge Society (2005) 684-694.
14. Skill Development: Bridging Skills Deficit and Promoting Employability, PHD Chamber of Commerce and Industry, ApeejaySatya Education Research Foundation http://www.aserf.org.in/presentations/ Conf-SKD-Backgrounder.pdf
15. Skill development Initiatives India brief overview http://www.academia.edu/7524653/ Skill_Development_Initiatives_I ndia_ rief_ overview_of_SkillDevelopment_Sector_In itiatives _in _ India _By_TABLE_OF_CONTENTS.
16. Grabe Mark & Grabe Cindy, "Integrating Technology for Meaningful Learning", (4th Ed.), Houghton Mifflin Company (2004).
17. Parsoya Shubham & Perwej Asif. Study of the Negative & the Positive Impact of Coronavirus Pandemic on Different Types of Industry, Businesses & the Society. *Wesleyan Journal of Research* **13**(69), 29-40.
18. Yash Pal Sharma,"SKILL DEVELOPMENT PROGRAMMES IN INDIA" November 1-12, 2010, http://www.b-able.in/Knowledge%20Bank/South%20South %20Study%20Visit% 20Report_YP%20 Sharma.pdf
19. www.makeinindia.com
20. Economic Times (e-paper)
21. Business Standard (e-paper).
22. The Hindu Business Line (e-paper)
23. Financial Express (e-paper)
24. Times of India (e-paper)
25. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, (FICCI 2013), Sandhya Srinivasan, Skill Development Initiatives in India, ISAS Special Report, No. 15-11 July 2013.
26. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Analysis of the Role and Importance of Information and Communication Technology (ICT) in Transforming the Present Education System of India: With Respect to "Revised Assessment and Accreditation Framework of NAAC".*Langlit*,(2021) 59-66.doi.org/10.5281/zenodo.4744288
27. Agarwal H & Pandey G N Impact of E-Learning in Education, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, **2**(12) (2013).
28. FICCI, Ernst and Young. Knowledge Paper on Skill Development Learner First (2012).
29. Perwej A P & Parsoya, S P, Sangam University Bhilwara, Rajasthan, & Karadeniz Technical University, Public Research University, Trabzon, Turkey, Significance of Technology and Digital Transformation in Shaping the Future of Oil and

Gas Industry, *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, **12**(3) (2012) 3345-3352.

30. Goyal S, Kaur P, & Singh K Role of HR and Financial Services in Making "Make in India" Campaign a Success, *IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM)*, **17** (2) (2015) 20-24.
31. UNESCO. (2012). The Positive Impact of e-Learning- 2012. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The%20Positive%2 0Impact%2 0 of % 20 eLearning% 202012 UPDATE_2% 206% 20121% 20(2).pdf
32. Green R A, December 15, 2014, Can "Make in INDIA" Make Jobs? The Challenges of Manufacturing Growth. Institute for Public Policy of Rice University, international Economics.
33. Goswami C (2014), Role of technology in Indian education. Retrieved from www.ipedr.com/vol79/002-IC4E2014-1-003.pd, doi-DOI: 10.7763/IPEDR.2014.
34. Perwej A P & Parsoya S P, Sangam University Bhilwara, Rajasthan, & Karadeniz Technical University, Public Research University, Trabzon, Turkey, Significance of Technology and Digital Transformation in Shaping the Future of Oil and Gas Industry. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), **12**(3) (2021) 3345-3352.https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1591
35. Kapooria D P, & Sambria S, Employability & skill gap, An overview of Literature Review, *International Journal of Marketing, Financial Service and Management Research*, **4**(2) (2015) 1-6.
36. Okada A, Skill Development for Youth in India: Challenges & Opportunities, *Journal of International Cooperation*, **15**(2) (2012) 169-193.
37. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Present requirements of drawing up necessary changes in our petroleum usage to alleviate the detrimental aftermath of environmental contamination, *Bharatiya Vaigyanik Evam Audyogik Anusandhan Patrika (BVAAP)*, NISCAIR Online Periodicals Repository (NOPR), ISSN: 0975-2412 (online), ISSN: 0771-7706 (print), UGC-CARE Listed Journal, BVAAP **29**(1) (2021) (1), 14-18.
38. Palit D A Skill Development in India: Challenges and Strategies. ISAS Working Paper (89) (2009).
39. Punjani P K (n.d.), A Study on the requirement of skills development for the success of MAKE IN INDIA project, *Tactful Management Research Journal*, 65-69.
40. Saini V, Skill Development in India: Need, Challenges and Ways Forward, *Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Arts & education*, **4**(4) (2015).
41. Parsoya, Shubham & Perwej Asif, Analysis of the Role and Importance of Information and Communication Technology (ICT) in Transforming the Present Education System of India: With Respect to "Revised Assessment and Accreditation Framework of NAAC".*Langlit*, an International Peer-reviewed Open Access Journal (ISSN 2349-5189), Special Issue, (2021) 59-66. S. &., Analysis of the Role and Importance of doi.org/10.5281/zenodo.4744288
42. S D, Kaul M, Goel E, & Narang V, Exploring prospects for Make in India and Made in India, A study, PHD Chamber of Commerce. GUJRAT: VIBRANT GUJRAT SUMMIT (2015).
43. Das A K Skill Development for SMEs: Mapping of Key Initiative in India, *Institutions and Economies*, **7** (2) (2015) 120-143.
44. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Strategic Industrial Business Contemplations and Prospective Marketing Approaches of Government in Controlling and Managing the Businesses of Oil Marketing Companies (OMCs): An Indian Perspective. In *ESN PUBLICATIONS* (An ISO 9001:2015 Registered Company): Vols. ISBN: 978-81-947019-0-3 (Number Special Issue, pp. 12013-12026). ESN PUBLICATIONS (An ISO 9001:2015 Registered Company).(Parsoya S. &., Strategic Industrial Business Contemplations and Prospective Marketing Approaches of Government in Controlling and Managing the Businesses of Oil Marketing Companies (OMCs): An Indian Perspective, 2021)https://doi.org/10.5281/zenodo.4742707

45. Planning Commission Working Group Report, 12th Five Year Plan 2012-2017 Secondary & Vocational Education. Planning Commission, Government of India (2011).

46. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Study of the Negative & the Positive Impact of Coronavirus Pandemic on Different Types of Industry, Businesses & the Society, *Wesleyan Journal of Research* **13**(69) (2021) 29-40.

47. Ministry of HRD. Guidelines for Implementation of National Vocational Education Qualification Framework for Implementation of NVEQF. New Delhi, India: Government of India (2014).

48. Government of India (2012), Reports and Publications, Ministry of Statistics and Programme Implementation. Government of India. New Delhi.

49. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Analysis of the Role and Importance of Information and Communication Technology (ICT) in Transforming the Present Education System of India: With Respect to "Revised Assessment and Accreditation Framework of NAAC", *Langlit*, an International Peer-reviewed Open Access Journal (ISSN 2349-5189), Special Issue (2021) 59-66.(Parsoya S. &., Analysis of the Role and Importance of Information and Communication Technology (ICT) in Transforming the Present Education System of India: With Respect to "Revised Assessment and Accreditation Framework of NAAC, 2021)https://doi.org/10.5281/zenodo.4744288

50. FICCI Ernst & Young. (September 2012). Knowledge Paper on Skill Development Learner First.

51. Saini V Skill Development in India: Need, Challenges and Ways Forward. Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Arts & Education, **4** (4) (2015).

52. Parsoya Shubham, Parsoya Priyanka, & Perwej Asif, Future Business Prospects and Marketing Strategies of Oil and Energy Marketing Companies (Under Government of India). *Vidyawarta*® Peer-reviewed International Journal; Interdisciplinary Multilingual Refereed Journal; MAH MUL/03051/2012, (ISSN: 2319 9318), Vol-09(Issue-33), (2020) 84-88.(Parsoya S. P., 2020)https://doi.org/10.5281/zenodo.4749296

53. Goyal S, Kaur P, & Singh K, Role of HR and Financial Services in Making "Make in India" Campaign a Success, *IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM)*, 17 (Issue 2.Ver. IV), 20-24.

54. Parsoya Shubham, & Perwej Asif, Analysis of the Marketing Strategies of Reliance Industries (Petroleum & Oil Company) In Enhancing Its Petroleum Business & Establishing as A Global-Level Petroleum Company. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)*, Volume: 04(Issue: 12) (2020) 4. (Parsoya S. &., Analysis of the Marketing Strategies of Reliance Industries (Petroleum & Oil Company) In Enhancing Its Petroleum Business & Establishing as A Global-Level Petroleum Company, 2020)https://doi.org/10.5281/zenodo.4743493

55. Green R A (December 15, 2014). Can "Make In India" Make Jobs? The Challenges of Manufacturing Growth, Institute for Public Policy of Rice University, International Economics.

56. Parsoya Shubham, & Perwej Asif, Study of the Role and Importance of Futuristic & Fast Transportation Technology in Shaping the Bright Future of India, *Wesleyan Journal of Research* | UGC Care-listed | ISSN: 0975-1386 | Peer-reviewed Journal, 13 (No. 65)(March 2021), 31-44.(Parsoya S. &., Study of the Role and Importance of Futuristic & Fast Transportation Technology in Shaping the Bright Future of India, 2021)https://doi.org/10.5281/zenodo.5329465

57. Jain P, Globalization and Developing Employability Skills: Challenges and their Solution with Reference to NPSD & Government's Action Plan and Role of Life Long Learning and Extension Departments, *Journal of Business Management & Social Sciences Research* (JBM & SSR), 2, 1-4.

58. Parsoya Shubham & Perwej Asif, Current Needs of Making Changes in Transportation and Energy Policies to Mitigate the Bad and Harmful Impacts of Environmental Pollution; An Indian Perspective. Printing Area, Peer-reviewed International Journal

(ISSN: 2394 5303), Vol-01(Issue-63) (2020) 83-87.(Parsoya S. &., Current Needs of Making Changes in Transportation and Energy Policies to Mitigate the Bad and Harmful Impacts of Environmental Pollution; An Indian Perspective, 2020)https://doi.org/10.5281/zenodo.4744661https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16547430.v2

59. Derrick L Cogburn, Globalization, Knowledge, Education and Training in the Information Age. Gibbons, M. (1998), "Higher education relevance in the 21st Century", paper presented at the UNESCO World Conference, Paris, October 5-9 (2000) pp. i-ii & 1-60.